

पीएम इंटरनशिप योजना



3 अक्टूबर को, केंद्र ने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉच किया है। यह बेरोजगारों के लिए बजट में की गई प्रमुख घोषणाओं में से एक को लागू करने के लिए मंच के रूप में काम करेगा।

कुछ बिंदु -

- यह पोर्टल पी एम इंटरनशिप योजना से जुड़ा है।
- यह रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, और पांच वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं को कौशल का प्रशिक्षण देने का एक माध्यम है।
- यह रोजगार के इच्छुक युवाओं को ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग देने के लिए तैयार कंपनियों से जोड़ेगा।
- इस ट्रेनिंग के बाद युवाओं को इंटरनशिप का प्रमाणपत्र दिया जाएगा। इससे उन्हें नौकरी पाने में प्राथमिकता मिल सकती है।
- इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत दिसंबर में 1.25 लाख इंटरन के पहले बैच से हो जाएगी।
- इस योजना का लक्ष्य 2029 तक एक करोड़ इंटरन तैयार करना है।

चुनौतियां -

- ड्रॉपआउट दरों और शिकायतों पर बारीकी से नजर रखनी होगी।

- इंटरन को उनके आसपास के क्षेत्रों में रखने की योजना है। बिहार जैसे कम औद्योगिक और कम सेवा-उन्मुख राज्यों में चुनौतियां बड़ी होंगी।
- भारत के विनिर्माण क्षेत्र में आधे से अधिक की हिस्सेदारी सिर्फ पांच राज्यों की है, और कम व्यावसायिक उपस्थिति वाले राज्यों में युवा बेरोजगारी अधिक है।
- शॉप फ्लोर कौशल के अलावा, इस योजना में डिजिटल और सॉफ्ट स्किल को शामिल करने की आवश्यकता है।
- पूरे प्रोजेक्ट को समय-समय पर निष्पक्ष और स्पष्ट मूल्यांकन की आवश्यकता होगी।

'द हिंदू' में प्रकाशित संपादकीय पर आधारित। 07 अक्टूबर, 2024

